



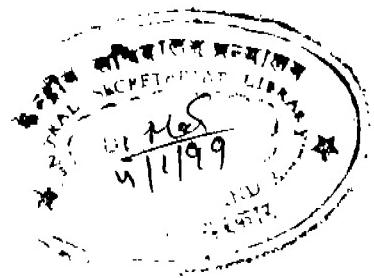
भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 285]
No. 285]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 1998/श्रावण 14, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 1998/SHRAVANA 14, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1998

सं. 24/98-के. उ. श.

सा. का. नि. 474 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 86 में आने वाले, शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र में किसी इकाई में उत्पादित अथवा विनिर्मित मैरिन फ्रेट कंटेनरों को, यदि उनकी भारत में निर्यात के लिए किसी की जाती है तो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्घाणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :—

बशर्ते कि इकाई तथा मैरिन फ्रेट कंटेनरों के क्रेता, शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रभारी सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे रूप में और ऐसी राशि के लिए एक बंधपत्र पर को निष्पादित करते हैं जिससे उनके लिए शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र से निकासी की सिधि से छ: माह के भीतर उक्त कंटेनरों का निर्यात करना बाध्यकारी हो तथा वे सीमाशुल्क सहायक आयुक्त की संतुष्टि के लिए एतदसंबंधी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे तथा यदि उक्त ग्राहक उक्त मैरिन फ्रेट कंटेनरों का निर्यात करने में असफल रहता है तो उस पर उद्घाणीय शुल्क का भुगतान करेगा

बशर्ते यह भी कि उक्त छ: माह की अवधि को पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा और छ: माह से अनाधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

[फाइल. सं. 305/96/97-एफटीटी]

सीमा जी जे, अवर सचिव

टिप्पणी : मैरिन फ्रेट कंटेनरों के घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए इस अधिसूचना द्वारा मैरिन फ्रेट कंटेनरों को, यदि शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों से इनकी निकासी छी. टी. ए. में निर्यात के लिए की जाती है तो, शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 1998

No. 24/98-CE

G.S.R. 474 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts marine freight containers, falling under Chapter 86 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), produced or manufactured in hundred per cent export oriented unit or a unit in an Export Processing Zone or a Free Trade Zone from the whole of the duty of excise leviable thereon under Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), when sold in India for export.

Provided the unit and buyer of the marine freight containers executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs in charge of the hundred per cent export oriented unit or Export Processing Zone or Free Trade Zone, binding themselves to export the said containers within six months from the date of clearance from the hundred per cent export oriented unit or Export Processing Zone or Free Trade Zone and to furnish documentary evidence thereof to the satisfaction of Assistant Commissioner of Customs and to pay the duty leviable thereon in the event of the failure of the said buyer to export the said marine freight containers:

Provided further that the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Assistant Commissioner of Customs for a further period not exceeding six months.

[F. No. 305/96/97-FIT.]

SEEMA G. JERE, Under Secy.

Note : To create a level playing field for the domestic manufacturers of marine freight containers the notification exempts the marine freight containers from payment of duty when cleared from 100% EOU's into DTA for exports.